भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *18
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या

18. श्री जॉन ब्रिटासः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितनी-कितनी महिला न्यायाधीश हैं ;

(ख) तत्संबंधी उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) महिला न्यायाधीशों और दलित तथा पिछड़े समुदायों से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किए जाने के मामले में सरकार का क्या रुख है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *18 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : तारीख 28.01.2022 तक, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद संख्या 34 के समक्ष 04 महिला न्यायाधीश कार्यरत है और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद संख्या 1098 के समक्ष 83 महिला न्यायाधीश कार्यरत है । तारीख 28.01.2022 तक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत महिला न्यायाधीशों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध** पर दिया गया है ।

(ग) और (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । तथापि, सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से यह अनुरोध किया जाता रहा है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाए ।

****

उपाबंध

"अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या" के संबंध में श्री श्री जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *18 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2022 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या	28.01.2021 तक महिला न्यायाधीशों की कार्यरत पद संख्या
क	भारत का उच्चतम न्यायालय	34	04
ख	उच्च न्यायालय		
1	इलाहाबाद	160	5
2	आंध्र प्रदेश	37	2
3	बॉम्बे	94	7
4	कलकत्ता	72	5
5	छत्तीसगढ	22	1
6	दिल्ली	60	6
7	गुवाहाटी	24	3
8	गुजरात	52	6
9	हिमाचल प्रदेश	13	2
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	17	1
1 1	झारखंड	25	1
12	कर्नाटक	62	6
13	केरल	47	6
14	मध्य प्रदेश	53	3
15	मद्रास	75	13
16	मणिपुर	5	0
17	मेघालय	4	0
18	उड़ीसा	27	1
19	पटना	53	0
20	पंजाब और हरियाणा	85	7
21	राजस्थान	50	1
22	सिक्किम	3	1
23	तेलंगाना	42	6
24	त्रिपुरा	5	0
25	उत्तराखंड	1 1	0
कुल		1098	83

****